बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 176 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 28 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

प्रधानमंत्री सिक्किम की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगे शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचेंगे और एक रोड शो करेंगे तथा राज्य की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मोदी यहां 4,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार, वह अपराह्न करीब तीन बजे गंगटोक पहुंचेंगे और लिबिंग हेलीपैड पर उतरने के तुरंत बाद वहां लोक भवन तक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री अगले दिन गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे।

जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में अब पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, बोले- न्याय मिलने की उम्मीद टूटी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपने पत्र में न्याय मिलने की उम्मीद टूटने की बात कहते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है। इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए फैसला किया है। जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रहीं जज स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को किसी दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी भी की और याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के

खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में पेश ही नहीं होने का एलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। हमें कई महीने जेल में रखा लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। कोर्ट ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले के हाई कोर्ट में चुनौती दी ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने लगा। तब मेरे मन में सवाल उठा कि क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज न्यायाधीश के समुख लिखने का प्रयास किया है हम उसकी निंदा करते हैं। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने इस पूरे मामले में देखा कि शराब घोटाला मामले में उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी न्यायाधीश पर की है ये लोकतंत्र के खिलाफ है।

जल रही राजधानी- दिल्ली में हीटवेव को लेकर एलजी सख्त, अधिकारियों से बोले- एक हफ्ते में जमीन पर दिखना चाहिए असर

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए उपरायपाल तरनजीत सिंह संधू ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर ठोस कदम जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। राजधानी में तेज होती गर्मी और हीट एक्शन प्लान 2026 का जमीन पर पालन नहीं होता देख एलजी ने संज्ञान लिया है। प्लान में शामिल तैयारियों पर प्रशासन ने अब तक शायद अमल नहीं किया है। हीट वेव से सबसे यादा तकलीफ बाहर काम करने वाले मजदूरों को हो रही है। बेसहारा पशु पक्षी भी तकलीफ में है। इनकी राहत के लिए जमीन पर कोई कार्यवाही अब तक नजर नहीं आ रही है। सोमवार को हीटवेव को लेकर दिल्ली के उपरायपाल ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा की गई और साफ निर्देश दिए गए कि हीट एक्शन प्लान को एक हफ्ते के भीतर

प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी

उपरायपाल ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट इस पूरे अभियान में अहम भूमिका निभाएं और अपने-अपने क्षेत्रों में समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। सार्वजनिक स्थानों पर गर्मी से राहत देने के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सभी विभाग मिलकर करेंगे काम

बैठक में यह भी तय किया गया कि हीटवेव से निपटने के लिए सभी विभाग आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और जागरूकता जैसे उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

पशु प्रेमी के लिए भी हो विशेष इंतजाम

उपरायपाल ने सिर्फ लोगों ही नहीं, बल्कि शहर के पशु-पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में इनके लिए पानी और राहत की व्यवस्था करना भी जरूरी है।

अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने की चेतावनी

साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं। सरकार इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी करेगी, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दिल्ली में हीटवेव से निपटने के लिए उपरायपाल ने निगरानी अपने पास रखी है, जिस कारण आने वाले दिनों में इसका असर जमीन पर दिखने की उम्मीद है।

अस्पतालों ने इलाज से क्यों किया इनकार? सीजेआई सूर्यकांत ने पूछे सवाल, पीड़ित महिला वकील के पत्र पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में महिला अधिवक्ता पर कथित बर्बर हमले के मामले का सोमवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को कई सख्त निर्देश दिए। अदालत ने मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया और कहा कि जांच अधिकारी महिला अधिकारी हो तो बेहतर होगा, जो एसीपी या डीसीपी रैंक की हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाला पत्र मिला था, जिसके बाद स्वतः संज्ञान लिया गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता के पति, जो हमले का मुख्य आरोपी है, को 25 और 26 अप्रैल की दरम्यानी रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी मनोज कुमार, जो सोनिया विहार का निवासी है, जिसे रविवार को खजूरी खास इलाके से पकड़ा गया। आरोप है कि उसने 22 अप्रैल को अपनी 38 वर्षीय पत्नी पर चाकू से हमला किया। पूछताछ में उसने पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर पहलू पर भी चिंता जताई। अदालत ने दिल्ली को निर्देश दिया कि यह जांच की जाए कि घायल महिला को तीन अलग-अलग अस्पतालों ने भर्ती करने से कथित रूप से इनकार क्यों किया। अदालत ने कहा कि अगर गंभीर हालत में किसी पीड़ित को समय पर इलाज नहीं मिलता है, तो यह बेहद चिंताजनक विषय है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीठ ने शिकायत में लगाए गए उस आरोप पर भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के ससुराल पक्ष दो नाबालिग बच्चों को अपने साथ ले गया है और उनका पता नहीं चल पा रहा। अदालत ने पुलिस को दोनों बच्चों का तत्काल पता लगाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने जांच अधिकारी को मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस घरेलू विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक एमसीडी के लिए नामित, 2026-27 के लिए करेंगे प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14 विधायकों को दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया है। इस फैसले को विधानसभा और एमसीडी के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 14 विधायकों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया है। यह नामांकन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है और इसकी अधिसूचना 27 अप्रैल को जारी की गई है। ये निर्णय दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(ब)(3) के तहत लिया गया है। इसके तहत विधानसभा के सदस्य एमसीडी के कामकाज में भाग लेकर स्थानीय स्तर के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकेंगे।

ये विधायक हुए नामित

नामित विधायकों में नरेला से राज करण खत्री, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, सदर बाजार से सोम दत्त और करोल बाग से विशेष रवि शामिल हैं। इसके अलावा मादीपुर से कैलाश गंगवाल, हरी नगर से श्याम शर्मा, बिजवासन से कैलाश गहलोत, पालम से कुलदीप सोलंकी और दिल्ली कैंट से आप विधायक विरेन्द्र सिंह कादयान को भी शामिल किया गया है। सूची में राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, छतरपुर से करतार सिंह तंवर और पडपडगंज से रविंद्र सिंह नेगी का नाम भी है। इन सभी विधायकों को अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए एमसीडी के कामकाज में भागीदारी करनी होगी।

सरकार-निगम के बीच और बढ़ेगा तालमेल

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस पहल का मकसद विधानसभा और नगर निगम के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। अक्सर देखा जाता है कि विकास कार्यों में विभागों के बीच समन्वय की कमी से देरी होती है, जिसे इस कदम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस नामांकन के बाद उम्मीद है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से जुड़े मुद्दे सीधे एमसीडी के सामने रखे जा सकेंगे और उनके समाधान में तेजी आएगी। साथ ही, जनता की समस्याओं को लेकर जवाबदेही भी बढ़ेगी।

गुरुग्राम बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और प्रभावित लोगों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक कार्रवाई से शिकायत है, तो वह उचित मंच पर अपनी बात रख सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि गुरुग्राम में कई स्थानों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आई हैं। यदि हाईकोर्ट इस मामले में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल क्यों दे। अदालत ने यह भी कहा कि पहले संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ पक्ष रखा जाना चाहिए। दरअसल, गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। डीएलएफ फेज-1, गोल्फ कोर्स रोड, साउथ सिटी समेत कई पॉश इलाकों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस दौरान रैंप, गार्ड रूम, बाउंड्री वॉल, फुटपाथों और सड़कों पर किए गए कब्जों को हटाया जा रहा है।एयह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद तेज हुई, जिसमें स्टिल्ट प्लस चार मंजिला निर्माण नीति पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद प्रशासन ने उन

निर्माणों और कब्जों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की, जो नियमों के खिलाफ बताए गए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिना नोटिस दिए कई वैध निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने, सार्वजनिक स्थलों को मुक्त कराने और शहरी नियोजन को सही ढंग से लागू करने के लिए जरूरी है। वहीं स्थानीय लोगों का एक वर्ग कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, जबकि कई निवासी इसे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जारी रहने की संभावना है, जहां प्रभावित पक्ष राहत की मांग कर सकते हैं।

कैलाश हिल्स हत्याकांड - राहुल मीणा को 7 दिन न्यायिक हिरासत, आईआरएस अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म और हत्या का मामला

दिल्ली। दिल्ली के कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस आरोपी राहुल मीणा को सोमवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को सात दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने तमाम साक्ष्यों को जुटा लिया है। आरोपी राहुल मीणा व युवती का मोबाइल बरामद कर पुलिस ने उनको फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया है। पुलिस उसकी जांच कर केस को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। पुलिस ने वारदात के सभी चश्मदीदों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। पता चला है कि आरोपी ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। वह बदला लेने और लूटपाट के इरादे से दिल्ली पहुंचा और उसने वारदात को अंजाम दिया। शुरुआत में तो आरोपी गलती होने की बात कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कैलाश हिल्स इलाके में इमारत की तीसरी फ्लोर पर आरोपी ने आईआरएस अधिकारी की बेटी की दुष्कर्म के बाद बहुत हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी ने घर में रखा कैश, जेवरात और अन्य सामान लूटकर फरार हो गया। वारदात का पता चलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने 15 टीम बनाकर देर शाम

को आरोपी राहुल मीणा को द्वारका इलाके के ओयो होटल से दबोच लिया। उसके पास से लूटा गया सामान भी बरामद हो गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार की। दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वरिष्ठ अधिकारी की बेटी (22) की उनके पूर्व नौकर ने दुष्कर्म के बाद मोबाइल फोन चार्जर की केबल से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राहुल मीणा (19) को डेढ़ महीने पहले रुपयों में हेराफेरी करने पर काम से हटाया गया था। पुलिस ने उसे द्वारका में होटल से गिरफ्तार कर लिया। युवती ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की थी। अभी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, युवती माता-पिता के साथ अमर कॉलोनी के कैलाश हिल स्थित बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। बुधवार सुबह 6 बजे उसके माता-पिता जिम गए थे और घरेलू सहायक के लिए चाबी घर के बाहर रख गए थे। युवती घर पर अकेली थी। माता पिता जब लौटे, तो उन्होंने बेटी को फर्श पर अचेत पाया।

उसे पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। राहुल को पैसों की हेराफेरी के शक डेढ़ महीने पहले ही नौकरी से निकाला गया था। आशंका है, इसी का बदला लेने के लिए राहुल ने वारदात की। सीसीटीवी फुटेज में वह दिखा, तो मामला खुला। वारदात के बाद वह घर से कीमती सामान भी चुरा ले गया।

नहीं छोड़ेंगे!

पूछता है भारत बल्कि पूछता है विश्व कि ये विरोधी, मोदी जी को क्या बिल्कुल चेला ही समझते हैं। बताइए, ट्रंप जी ने अपने सोशल मीडिया पर भारत को जरा सा नर्क कुंड उर्फ हैल होल क्या लिख दिया, बस मोदी जी के पीछे पड़ गए कि इसका जवाब क्यों नहीं देते? जैसे को तैसा जवाब क्यों नहीं देते? अब भी जवाब नहीं देंगे तो क्या कहने पर जवाब देंगे, वगैरह, वगैरह। फिर यह मानकर कि मोदी जी इस बार भी मुंह नहीं खोलेंगे, इस पर बहस भी करने लगे कि ट्रंप ने इसी बयान में भारतीयों को लैपटॉप वाले आतंकवादी भी कहा था। उसने तो भारतीयों पर इसका भी इल्जाम लगाया था कि वे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका में आ जाते हैं और इन बच्चों को क्योंकि खुद ब खुद नागरिकता का अधिकार मिल जाता है, बाद में उनकी उंगली पकड़ कर उनके मां-बाप, दादा-दादी सब अमेरिका में आ धमकते हैं! यह तो भारत का घोर अपमान है। मोदी जी अब भी जवाब नहीं देंगे, तो कब देंगे? जब ज्यादा ही हाय-हाय होने लगी तो मोदी जी के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा पहले तो इसका नोटिस लेने के बाद भी, इस पर दो शब्द तक खर्च करने से इंकार कर के, इशारे में नापसंदगी का इजहार कर दिया। उससे भी काम नहीं चला तो बाकायदा इस सब को अनुचित, अनुपयुक्त बताते हुए, भारत के साथ अमेरिका के असली रिश्ते की याद भी दिला दी। पर विरोधियों को इससे भी संतोष नहीं हुआ। उन्हें तो मोदी जी के जवाब से कम कुछ मंजूर ही नहीं था। जैसे मोदी जी के पास ऐसी बातों के जवाब देने के अलावा और कोई काम ही नहीं हो। लेकिन, सच इससे ठीक उल्टा है। जिस शाम को ट्रंप का ताजा वाला बयान आया, मोदी जी ने खुद बताया कि वह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर विशाल रोड शो में व्यस्त थे। और अगली सुबह तो जैसा कि खुद मोदी जी ने वीडियो डालकर पूरे देश को दिखाया, मोदी जी सुबह-सुबह हुगली में नौका की सैर का आनंद ले रहे थे। और उसके बाद, जादवपुर विश्वविद्यालय को छात्र-राजनीति से मुक्त कराने का वादा कर रहे थे। (शुक्र है, छोटा भाई की तरह वह छात्र-कार्यकर्ताओं को उल्टा कर के सीधा करने का वादा करने तक नहीं गए।) और फिर तृणमूल के दीपक के बुझने से पहले फड़फड़ाने की भविष्यवाणियां कर रहे थे। अब मोदी जी देश और भारतीय संस्कृति की सेवा करें और हिंदुओं की रक्षा करें या सोशल मीडिया से आए इसके-उसके बयानों का जवाब देते फिरें? विरोधी तो जाहिर है कि यह चाहते ही हैं कि मोदी जी का ध्यान, चुनाव में देश की सेवा की तरफ से हट जाए और मोदी जी के चुनावी अश्वमेध का घोड़ा, इस बार भी कोई छाप पकड़ कर ले जाए। और फिर मोदी जी को राज्यपाल से लेकर सारी एजेंसियों के जरिए से, अपना अश्वमेध का घोड़ा छुड़वाने के लिए पांच साल तक लड़ाई लड़नी पड़े। बेशक, हमेशा मोदी जी को पांच साल इंतजार करना ही पड़ता हो ऐसा भी नहीं है। कई बार जो घोड़ा युद्ध से नहीं छुड़ाया जा सकता है, उसे खरीद-फरोख्त से छुड़ाने का भी जुगाड़ बन सकता है। जैसे इस वक्त पंजाब में बनता लग रहा है। आम आदमी पार्टी के दस में सात राज्यसभा सांसदों के मोदी-पार्टी में आने की मिठाई खाने के बाद, अब देश की सेवा के लिए पंजाब की सरकार आप पार्टी से छुड़ाने की तैयारी है। बंगाल के चुनाव से निपटते ही, मोदी जी-शाह जी पंजाब के रण में लगेंगे। बेशक, बंगाल के रण में लगे हुए भी, वह पंजाब के लिए समय बिल्कुल ही नहीं निकाल रहे हों, ऐसा भी नहीं है। मोदी जी और शाह जी, कई मोर्चे एक साथ संभालना बखूबी जानते हैं। पर अब पंजाब के रण में फुलटाइम लगेंगे। सीबीआइ, ईडी, आयकर, अदालत, चुनाव आयोग सब के साथ। महाराष्ट्र में शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की मिल्कियत का मुकदमा तो याद होगा; वैसे ही राज्यसभा के सभापति से लेकर, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग तक, बंटवारे का मुकदमा कम से कम पंजाब में अगली सरकार बनने तक तो मोदी जी-शाह जी को व्यस्त रखेगा ही! हमें पता है कि विरोधी जरूर कहेंगे कि यह सिर्फ चुनाव में व्यस्तता की बात नहीं है। यह तो मोदी जी का कायदा ही हो गया है। बार-बार उनका डियर फ्रेंड ट्रंप भारत का और भारतीयों का अपमान करता है। और मोदी जी के मुंह से डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड के सिवा दूसरा बोल ही नहीं निकलता है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ लुटेरा कह दिया, मोदी जी डियर, डियर करते रह गए। ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ी-बेड़ियां लगाकर अपने फौजी जहाजों से वापस भेजा, जब मोदी जी अमेरिका में थे, तब भी ऐसे ही भारतीयों को वापस भेजा, मोदी जी के विदेश मंत्री उसे अमेरिका का अपने नियमानुसार काम करना बताते रह गए। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माने के तौर पर 25 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, मोदी जी रूस से तेल खरीदना करीब-करीब बंद करने के बाद, उसके सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, पर फूलकर कुप्पा होते रहे। ट्रंप ने भारत पर पूरी तरह से इकतरफा व्यापार समझौता थोप दिया, मोदी जी अमेरिका से सहयोग बढ़ने के सपने देखते और दिखाते रहे। और ट्रंप ने जब ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का दावा कर दिया, मोदी जी बगलें झांकते रह गए। यह तो मोदी जी की आदत ही हो गयी है ट्रंप भले अपमान पर अपमान करता रहे, मोदी जी खुशामद ही करते रहेंगे। पर मोदी जी का डियर फ्रेंड तो इतने पर भी खुश नहीं है। खुद आरएसएस-भाजपा के साझा थिंक टैंक, राम माधव ने अमेरिका में जाकर पूछ दिया कि मोदी जी अब और क्या करें, जिससे ट्रंप जी खुश हो जाएंगे! अमेरिका ने कहा, रूस से तेल मत खरीदो, मोदी जी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगा दिया, मोदी जी ने चूं भी नहीं की। व्यापार समझौते में भारत पर 18 फीसद टैरिफ लगा दिया, जो पहले औसतन 3 फीसद था, देश में बहुत विरोध हुआ, पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी और क्या करें, जिससे ट्रंप को संतोष हो जाए कि भारत उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ कर रहा है। पर विरोधियों के इस संतोष वाले आइडिया में ही प्रॉब्लम है।

ज्ञानेश कुमार फिर 'घेरे' में

भारत के संविधान में सुभाषित जिस सिद्धान्त के आधार पर चुनाव आयोग का गठन किया गया उसमें इस संस्था की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता निर्द्वन्द्व इस प्रकार रखी गई कि भारत के चुनावों में भाग लेने वाले हर राजनैतिक दल के साथ एक समान व्यवहार हो और सभी के लिए अनुशासन व राजनैतिक नैतिकता का पैमाना बराबर हो। ये मानक लागू करते समय चुनाव आयोग को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सा दल सत्ता में है और कौन सा विपक्ष में। उसके लिए चुनावों में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला हर राजनैतिक दल लोक प्रतिनिधि होता है और वह उसे इसी नजर से देखता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी वजह से चुनाव आयोग को सरकार का अंग नहीं बनाया और इसे संविधान से शक्तियां लेकर अपना कार्य संचालन करने के लिए अधिकृत किया। यह व्यवस्था इसलिए है कि जब किसी राज्य में चुनाव घोषित हो जाते हैं तो पूरी प्रशासन प्रणाली चुनाव आयोग के नियन्त्रण में आ जाती है और वहां की सत्तारूढ़ सरकार केवल एक राजनैतिक दल की नुमाइंदगी करने लगती है। चुनावों में मुख्यमन्त्री से लेकर किसी मन्त्री के चुनाव का खर्चा उसकी पार्टी ही उठाती है, बेशक उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकारी खर्चे से ही होती है क्योंकि वे संवैधानिक पदों पर होते हैं। ठीक यही व्यवस्था लोकसभा चुनाव होने पर पूरे राष्ट्र में लागू होती है। अतः लोकतन्त्र में यह बहुत आवश्यक होता है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार के शक के दायरे से ऊपर रहे और उस पर एक आदमी से लेकर प्रधानमन्त्री तक का अटूट विश्वास रहे। मगर सितम यह है कि जब से श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं तभी से लगातार वह विवादों में घिरे हुए हैं और देश के विपक्षी दल उन पर पक्षपात करने व संवैधानिक संस्था के मुखिया होने के नाते उसके अनुरूप आचरण न करने के आरोप लगा रहे हैं। यह स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है क्योंकि किसी भी स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था के मुखिया से अपेक्षा की जाती है कि उसका आचरण शक के घेरे से बाहर इस प्रकार होगा कि वह सद्व्यवहार का जीता-जागता प्रमाण हो जिसे उर्दू में 'सादिक-अमीन' कहा जाता है। चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच सरकार कहीं नहीं आती है क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली से उसका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता है। इसलिए लोकतन्त्र में चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने की जिम्मेदारी सीधे संसद को ही दी गई है। बेशक संसद द्वारा बनाये गये नये कानून के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार ही लोकसभा में विपक्ष के नेता की उपस्थिति के बीच करती है परन्तु नियुक्ति समिति में सरकार का ही बहुमत होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले भी सरकार ही नियुक्त करती थी हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति की कलम से ही की जाती है परन्तु मुख्य चुनाव आयुक्त को पद मुक्त करने का विधान पहले भी उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाना ही था। हमने देखा है कि किस प्रकार पिछले महीने लोकसभा व राज्यसभा में श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाये गये महाभियोग के नोटिसों को इन दोनों सदनों के अध्यक्षों ने अस्वीकार कर दिया था। तब ये नोटिस राज्यसभा व लोकसभा के सांसदों द्वारा दिये गये थे और इन पर कुल 190 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे। ये नोटिस इसलिए दिये गये थे कि श्री ज्ञानेश कुमार अपने पद के अनुरूप न आचरण कर रहे थे और न विपक्षी दलों के प्रति निष्पक्षता बरत रहे थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि वे सत्तारूढ़ दल भाजपा के पक्ष में रहते हैं और उसके खिलाफ। ये नोटिस स्वीकृत नहीं हुए थे मगर विपक्षी दलों ने तभी कहा था कि वे राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष के इस सन्दर्भ में किये गये फैसले से पूरी तरह असहमत रहते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिसों का संज्ञान संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं लिया है, अतः वे इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक में ले जा सकते हैं। विपक्षी दल सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं गये मगर पांच राज्यों में चुनाव घोषित होने के बाद श्री ज्ञानेश कुमार व चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उन्होंने राज्यसभा में श्री कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने का नया नोटिस इसके महासचिव को सौंप दिया है। इस नोटिस में श्री कुमार के खिलाफ नौ विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं और कहा गया है कि उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई राज्यसभा में शुरू की जाये। इस बार महाभियोग शुरू कराने की कमान कांग्रेस पार्टी के नेता श्री जयराम रमेश ने संभाली है जबकि पिछली बार कमान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हाथ में थी। बेशक प. बंगाल के चुनाव में कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के आमने-सामने हैं मगर इस मुद्दे पर उनमें एका है। नोटिस पर राज्यसभा के 73 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जो विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य हैं। नोटिस देने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर ही काफी होते हैं। इस बार के नोटिस में आरोपों को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है और कहा गया है कि श्री ज्ञानेश कुमार प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री के इशारों पर चल रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता लागू करने के मामले में भेदभाव किया। मोटे तौर पर इसका मतलब निकाला जा सकता है कि वह चेहरा देख कर चपत लगाते हैं। उनका आचरण पद की प्रतिष्ठा व गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक में सद् व्यवहार नहीं किया और उल्टे पार्टी का नाम लेकर इसे भली- बुरी सार्वजनिक रूप से सुनाई। इस प्रकार कुल नौ आरोप हैं। देखना केवल यह है कि अब इस नोटिस का हश्र क्या होता है।

वैसे कानून कहता है कि आरोपों की जांच के लिए पहले राज्यसभा के सभापति को एक खोजी-जांच समिति गठित करनी चाहिए और फिर उसकी रिपोर्ट पर अपनी कोई राय बनानी चाहिए। इस बार तो आरोप बहुत विशिष्ट भी हैं।

सम्पादकीय...

सरकार जी के रात 8 और 8.30 बजे के संबोधन का अंतर

इस बार सरकार जी ने रात के साढ़े आठ बजे राष्ट्र को संबोधित किया। यह समय अपने आप में ऐतिहासिक था। सरकार जी का राष्ट्र को संबोधन सामान्यतः रात आठ बजे होता है। आठ बजे वाले संबोधन वे होते हैं जिनके बाद जनता की नींद उड़ जाया करती है–जैसे नोटबंदी, लॉकडाउन वगैरह। साढ़े आठ बजे वाले संबोधन जनता के लिए सुरक्षित मान सकते हैं; इनमें विपक्ष की नींद उड़ाई जाती है। काम की भाइयों और बहनों रात आठ बजे होती है, और चुनावी काम को भाइयों और बहनों साढ़े आठ बजे। आज मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। नारी सम्मान के लिए मेरा समर्पण किसी से छिपा नहीं है। मैंने नारी वंदन विधेयक 2023 में पारित कराया, अधिनियम भी बन गया, लेकिन मेरा मन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। मैं उसे फिर से पारित कराना चाहता था, ताकि इतिहास में यह दर्ज हो कि एक ही बिल को दो बार पास कराने का साहस भी केवल मुझमें है। परंतु कांग्रेस ने इसमें भी बाधा डाल दी। कांग्रेस की यही पुरानी आदत है। उसने न स्वयं कुछ अच्छा किया, न ही किसी और को करने दिया। आज़ादी से पहले भी उसने आरएसएस को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया था, और आज भी वह यही कर रही है। नारी सशक्तिकरण के श्रेय में साझेदारी नहीं करने देना चाहती है। सरकार जी ने आगे बताया कि कांग्रेस के शासन में महिलाएँ इतनी असुरक्षित थीं कि पति विवाह के बाद पत्नी को छोड़कर जा सकता था। पर आज स्थिति बदल चुकी है। अब अगर कोई छोड़कर जाता भी है, तो लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उसके जीवन पर जीवनियाँ लिखी जाती हैं। उन्होंने बड़े दर्द से कहा कि कांग्रेस के शासन में न तो माँ को इतनी स्वतंत्रता थी कि वह अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवा सके और न ही बेटा माँ के साथ फोटो खिंचवा सकता था। वे स्वयं इस अन्याय के भुक्तभोगी रहे हैं। बचपन, युवावस्था–कहीं भी माँ के साथ उनकी कोई तस्वीर नहीं मिलती है। जो भी तस्वीरें मिलती हैं, उनके सरकार जी बनने के बाद की ही मिलती हैं। कितना अन्याय था माँओं के साथ कांग्रेस के उस दौर में। और यह कहते हुए सरकार जी की आँसू टपक पड़े। फिर सरकार जी नारी की निजता पर आए। उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी सरकार के पिछले बारह वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री को किसी महिला की जासूसी करते हुए नहीं पकड़ा गया जैसा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। अब नारी की निजता का इतना सम्मान है कि यदि कभी किसी महिला की जासूसी का कोई कार्य आवश्यक हुआ, तो वह भी केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत, पूरी पारदर्शिता के साथ, उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष के नेता आचरण पर भी गंभीर प्रश्न उठाया–वे संसद में टी-शर्ट पहनकर क्यों आते हैं, जबकि उनकी कुछ महिला सांसदों को यह पसंद नहीं है। यह केवल ड्रेस कोड का मामला नहीं, यह नारी सम्मान का प्रश्न है। संसद की गरिमा, भारतीय संस्कृति और कपड़े की मोटाई–तीनों दाँव पर लगे हैं। सरकार जी ने भावुक होकर कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएँ उन्हें इतना विचलित कर देती हैं कि वे बोल ही नहीं पाते हैं। उन्नाव पर वे मौन रहे, हाथरस पर मौन रहे, बिलकिस बानो के बलात्कारियों को छोड़े जाने पर भी मौन रहे। उनका मौन ही उनका वक्तव्य था।

भाजपा का लक्ष्य सदा के लिए सत्ता में बने रहना

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भारत की किसी भी अन्य पार्टी, चाहे वह अतीत की हो या वर्तमान की, से अलग है। इसका लक्ष्य केवल अधिक से अधिक बार चुनाव जीतना नहीं, बल्कि चुनाव जीतना और हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना है। इस लिहाज से भाजपा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.सी.) की तरह है। सी.पी.सी. का सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक क्रूर युद्ध और 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद, 1949 में कुओमिन्तांग (के.एम.टी.) के खिलाफ एक कड़वे गृहयुद्ध के माध्यम से था। सी.पी.सी. तब से सत्ता में बनी हुई है। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान कई राजनीतिक दलों की अनुमति देता है और संघ-स्तर तथा राज्य-स्तर पर समय-समय पर चुनाव और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आदेश देता है। चीन और भारत के बीच यही महत्वपूर्ण अंतर है। भाजपा और आर.एस.एस.- अपनी स्थापना के समय जनसंघ और बाद में भारतीय जनसंघ और अपने वर्तमान स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी, भारत के संविधान में विश्वास करती थी। इसका पोषण एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में किया गया था और इसे राजनीतिक स्पैक्ट्रम के दक्षिणपंथी छोर पर रखा गया था। इसने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग करने का प्रयास किया, जिसने वाम-मध्य (लेफ्ट-ऑफ-सैंटर) स्थान पर कब्जा कर रखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ए.बी. वाजपेयी और एल.के. अडवानी के नेतृत्व में भाजपा वर्षों तक एक लोकतांत्रिक पार्टी बनी रही। हालांकि, भाजपा के राजनीतिक गुरु, आर.एस.एस. का भारत की राजनीति और राजनीतिक वास्तुकला के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था, और है। आर.एस.एस. का मानना है कि भारत एक भाषा, एक संस्कृति, एक राजनीतिक दल और जहां तक संभव हो, एक धर्म वाला देश होना चाहिए।

प्रधानमंत्री और भाजपा के वास्तविक (डी फैक्टो) नेता नरेंद्र मोदी एक ऐसे विचारक हैं जो भारत के बारे में आर.एस.एस. के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं लेकिन साथ ही, वह यह महसूस करने के लिए पूरी तरह से व्यावहारिक हैं कि आर.एस.एस. का लक्ष्य केवल चुनावी जीत के माध्यम से नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक तैयार किए गए कदमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 2014 से मोदी सरकार द्वारा उठाए गए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक कदमों को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और समान नागरिक संहिता का मोदी द्वारा पुरजोर समर्थन, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का पारित होना, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 और संविधान के भाग XI, XII और XIV के प्रावधानों की रचनात्मक व्याख्या और 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (ओ.एन.ओ.ई.) को लागू करने का दृढ़ प्रयास, ये सभी तथाकथित 'विकसित भारत' की शुरुआत करने के लिए गणना किए गए कदम हैं। अपेक्षा और निराशा – 2014 से 2024 तक मोदी का वर्चस्व था। उन्हें पूरे विश्वास के साथ उम्मीद थी कि भारत के लोग 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी को लोकसभा में 400+ सीटें देंगे लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका लगा, लोगों ने उन्हें केवल 240 सीटें दीं, जो कि 543 सीटों के साधारण बहुमत से भी कम है। 2024 के बाद से उनके सभी प्रयास 2029 से पहले खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए हैं। मान लीजिए कि भाजपा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने में सफल हो गई होती। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की आड़ में, इसने परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों में हेरफेर की अनुमति दे दी होती। नए कानून दक्षिण भारतीय राज्यों को देश के शासन में अप्रासंगिक बना देते। इसके अलावा, भाजपा 2029 में ओ.एन.ओ.ई. की अवधारणा को लागू करने के लिए विधेयक (विधेयकों) सहित संविधान के अन्य संशोधनों को पारित करने के लिए संसद में दबाव डालती। 2024 के लोकसभा चुनावों तक, भाजपा ने सोचा था कि उसके पास चुनाव जीतने का एक विजयी फार्मूला है-9 इकहरी भाषी राज्यों और गुजरात में एक क्रूर संगठनात्मक मशीन, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू के जिलों जैसे हिंदी जानने वाले राज्यों में एक उचित रूप से फिट पार्टी, धन शक्ति, आज्ञाकारी राज्यपाल, डरा हुआ नौकरशाही ढांचा, तलाशी लेने, जब्त करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की शक्ति वाली दब्बू जांच एजैंसियां, एक कब्जे में लिया गया या पालतू मीडिया, भारत के चुनाव आयोग का मौन समर्थन और एक संयमित न्यायपालिका। पूर्ण सत्ता की राह में बाधाएं दक्षिण भारतीय राज्य और पश्चिम बंगाल हैं। ओ.एन.ओ.ई. विधेयक को हराना होगा - मुझे डर है कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक यदि पारित हो जाता है, तो यह विपक्षी गुट को छिन्न-भिन्न कर सकता है। क्षेत्रीय और एक-राज्यीय दल कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी गुट बनाते हैं।

उनके आपस में मतभेद हैं और वे राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। साथ ही, उनमें लोकसभा चुनाव में एक गुट बनाने की क्षमता है, जैसा कि उन्होंने 2024 में किया था। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं (और अंततः स्थानीय निकायों) के चुनाव एक साथ होते हैं, तो क्षेत्रीय दलों के लिए एक साथ आना और एक गुट बनाना बेहद मुश्किल होगा, जो अकेले उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का सबसे अच्छा मौका देता है। ओ.एन.ओ.ई. उस महत्वाकांक्षा पर पानी फेर देगा। इसलिए, भाजपा ओ.एन.ओ.ई. विधेयक पारित होना अपने भव्य डिजाइन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखती है। 2024 के लोकसभा चुनावों का सबक यह है कि कई दलों द्वारा 'इंडिया' ब्लॉक बनाने के बावजूद, वे भाजपा को नहीं हरा सके, जो 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आपसी तालमेल के साथ, 'इंडिया' ब्लॉक में खुद को विस्तार देने की क्षमता है। यदि दल इस सबक को नहीं सीखते, तो कई छोटी पार्टियां पीछे छूट जाएंगी और गायब हो सकती हैं। अंततः, लोकसभा चुनाव में 2 बड़े गठबंधन केंद्र में भाजपा द्वारा सत्ता के एकाधिकार को रोकेंगे, वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प पैदा करेंगे और भारत के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक संविधान को बनाए रखेंगे।-पी. चिदम्बरम

भाजपा और आर.एस.एस.- अपनी स्थापना के समय जनसंघ और बाद में भारतीय जनसंघ और अपने वर्तमान स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी, भारत के संविधान में विश्वास करती थी। इसका पोषण एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में किया गया था और इसे राजनीतिक स्पैक्ट्रम के दक्षिणपंथी छोर पर रखा गया था। इसने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग करने का प्रयास किया, जिसने वाम-मध्य (लेफ्ट-ऑफ-सैंटर) स्थान पर कब्जा कर रखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ए.बी. वाजपेयी और एल.के. अडवानी के नेतृत्व में भाजपा वर्षों तक एक लोकतांत्रिक पार्टी बनी रही। हालांकि, भाजपा के राजनीतिक गुरु, आर.एस.एस. का भारत की राजनीति और राजनीतिक वास्तुकला के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था, और है। आर.एस.एस. का मानना है कि भारत एक भाषा, एक संस्कृति, एक राजनीतिक दल और जहां तक संभव हो, एक धर्म वाला देश होना चाहिए।

आखिर दुनिया का थानेदार ट्रंप और उनका अमेरिका खुद इतना असुरक्षित क्यों है?

संचार, तकनीकी और मानवीय चूकें; कोई बड़ा अधिकारी बर्खास्त नहीं, सिर्फ 6 पर हल्की कार्रवाई। इसलिए सिफारिशें की गईं कि जिम्मेदारों को दंडित करने, सुरक्षा सुधार और तालमेल मजबूत करने की मांग की। चेयरमैन रैंड पॉल ने इसे पूरी विफलता बताया। सीक्रेट सर्विस ने स्वीकार किया और सुधार शुरू किए। सीक्रेट सर्विस ने 2024 ट्रंप हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की चूक के बाद कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें एजेंटों पर कार्रवाई और प्रक्रियागत बदलाव शामिल हैं। ये कदम सीनेट रिपोर्ट (2025) के बाद तेज हुए। वहीं, एजेंटों पर कार्रवाई हुई। 6 एजेंटों को सस्पेंड किया, 10-42 दिनों की सैलरी कटौती और गैर-ऑपरेशनल पदों पर स्थानांतरित। पूर्व डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दिया। वहीं, प्रक्रियागत सुधार किए गए। स्थानीय पुलिस/एजेंसियों के साथ समन्वय, संचार और सुरक्षा मैनुअल को संशोधित। हवाई निगरानी के लिए अलग डिवीजन, खतरे मूल्यांकन में स्पष्ट जिम्मेदारियां। कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया।

कमलेश पांडे।

आखिर दुनिया का थानेदार कहे जाने वाला अमेरिका खुद असुरक्षित क्यों दिखता है? असल में यह एक मिथक और हकीकत का मिश्रण है। अमेरिका के नेता, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के असुरक्षित दिखने के पीछे कई परतें होती हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी वाले स्थल पर यह तीसरा बड़ा हमला है। इसलिए यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक, संस्थागत और वैश्विक कारणों का मिश्रण है। पहला, वैश्विक नेतृत्व का दबाव अमेरिका लंबे समय से खुद को विश्व नेतृत्व की भूमिका में रखता है। जब कोई देश या नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तो हर निर्णय पर आलोचना और चुनौती स्वाभाविक होती है-चाहे वह शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था हो या आज की बहुध्रुवीय दुनिया, अमेरिका ने हर चुनौतियों से सीखा और बेहतर समाधान देने की कोशिश की। दूसरा, घरेलू राजनीति की तीखी प्रतिस्पर्धा - डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति बहुत ध्रुवीकृत रही है। अमेरिका के अंदर ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच तीखी टकराहट, मीडिया की आलोचना, और चुनावी दबाव–ये सब किसी भी नेता को रक्षात्मक या असुरक्षित दिखा सकते हैं। तीसरा, कानूनी और व्यक्तिगत विवाद- ट्रंप कई कानूनी मामलों, जांचों और विवादों से घिरे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क–कभी-कभी असुरक्षित–दिख सकता है। चौथा, बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन- अब दुनिया एकध्रुवीय नहीं रही। चीन, रूस जैसे देश चुनौती दे रहे हैं। इससे अमेरिका की थानेदार वाली स्थिति पहले जैसी निर्विवाद नहीं रही, और यह असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। पांचवां, पॉपुलिस्ट (जनप्रिय) राजनीति की शैली - ट्रंप की राजनीति में हम बनाम वे का नैरेटिव मजबूत रहा है। इस शैली में नेता अक्सर खतरे को बड़ा दिखाते हैं–चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक–ताकि समर्थकों को एकजुट रखा जा सके। इसमें भी असुरक्षा का आभास होता है। छठा, असुरक्षा का एहसास बनाम असली आंकड़े- अमेरिका में लंबे समय में अपराध दर घटी है, खासकर 1990 के बाद से, लेकिन फिर भी लगभग 46% लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी समस्या सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि डर का माहौल भी है कारण स्पष्ट है कि मीडिया, सोशल मीडिया, और मास शूटिंग जैसी घटनाएं लोगों के दिमाग में डर बढ़ाती हैं। सातवां, आर्थिक असमानता- अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देशों में है, लेकिन अमीर-गरीब का अंतर बहुत बड़ा है बेरोजगारी, घर विहीनता, opioid crisis जैसी समस्याएं अपराध को बढ़ाती हैं। जहां असमानता ज्यादा होती है, वहां अपराध और असुरक्षा भी ज्यादा होती है। आठवां, हथियार संस्कृति- अमेरिका में आम नागरिक के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं। इससे छोटी घटनाएं भी घातक बन सकती हैं, जैसे शूटिंग इंसीडेंट्स। यही कारण है कि हिंसात्मक अपराध का डर ज्यादा रहता है। नौवां, अपराध का केंद्रित होना- पूरे अमेरिका में समान खतरा नहीं है, बल्कि अपराध कुछ खास शहरों या इलाकों में ज्यादा केंद्रित होता है।। इसलिए- कुछ जगह बहुत सुरक्षित है पर कुछ जगह बहुत खतरनाक। दसवां,, मीडिया और राजनीति का प्रभाव- लगातार चौबीस घण्टे सातों दिन न्यूज और सोशल मीडिया खतरे को अम्प्लीफाय करते हैं। लोग वास्तविकता से ज्यादा डर महसूस करते हैं। भय अर्थव्यवस्था भी एक फैक्टर है। ग्यारहवां, पुलिस और सिस्टम की सीमाएँ- अमेरिका पुलिस और जेल पर बहुत खर्च करता है, फिर भी मूल कारणों, जैसे- गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए सुरक्षा का ढांचा प्रतिक्रियावादी है, सुरक्षात्मक/संरक्षात्मक कम। बारहवां, सामाजिक व्यवहार और जीवनशैली- सड़क हादसे, नशा, मानसिक तनाव–ये भी असुरक्षा के बड़े कारण हैं कई मामलों में व्यवहार भी जिम्मेदार है। निष्कर्षतः- यह कहा जा सकता है कि अमेरिका कमजोर नहीं है, लेकिन- आर्थिक असमानता, हथियार संस्कृति, सामाजिक तनाव और मीडिया द्वारा बढ़ा डर आदि के कारण एक शक्तिशाली देश भी अंदर से असुरक्षित महसूस करता है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप की हालिया सुरक्षा चूक व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर (25 अप्रैल 2026) के दौरान हुई, जब एक संदिग्ध ने होटल में घुसकर गोली चलाई। अमेरिकी अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित समय सारिणी घोषित नहीं की गई है। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर के दौरान एक संदिग्ध (कोल एलन) ने शॉटगन, पिस्तौल और चाकू लहराते हुए सिक्योरिटी चेकपॉइंट तोड़ा और गोली चलाई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत नेताओं को सुरक्षित निकाला; एक एजेंट को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ वेस्ट से बच गया। बहरहाल, जांच की स्थिति यह है कि FBI की एंटी-टेरर यूनिट जांच लीड कर रही है, जिसमें हथियार, गवाह बयान और संदिग्ध के मैनिफेस्टो की पड़ताल शामिल है। एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि संदिग्ध ट्रंप व उनकी टीम को टारगेट बना रहा था, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। ट्रंप ने इसे सिक्योरिटी सक्सेस बताया, पर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठे हैं। आखिर जवाब कब? तो अधिकारियों ने लाइव अपडेट दिए हैं, लेकिन सुरक्षा चूक के सवालों (जैसे चेकपॉइंट कैसे टूटा) पर कोई अंतिम रिपोर्ट या सुनवाई की तारीख की घोषणा नहीं हुई। जांच जारी है, अतिरिक्त विवरण आने पर बयान संभव। इससे पहले ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 के हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की जांच में जुलाई 2025 में जारी अमेरिकी सीनेट रिपोर्ट ने सीक्रेट सर्विस की गंभीर चूक उजागर की। यह 2026 की हालिया घटना से जुड़ी नहीं, बल्कि पुरानी घटना पर आधारित है। मुख्य निष्कर्ष यह है कि विश्वसनीय खुफिया सूचना के बावजूद सीक्रेट सर्विस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की; खतरे को नजरअंदाज किया। वहीं, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय की कमी, खासकर पास की छत को सुरक्षित न करना। संचार, तकनीकी और मानवीय चूकें; कोई बड़ा अधिकारी बर्खास्त नहीं, सिर्फ 6 पर हल्की कार्रवाई। इसलिए सिफारिशें की गईं कि जिम्मेदारों को दंडित करने, सुरक्षा सुधार और तालमेल मजबूत करने की मांग की। चेयरमैन रैंड पॉल ने इसे पूरी विफलता बताया। सीक्रेट सर्विस ने स्वीकार किया और सुधार शुरू किए। सीक्रेट सर्विस ने 2024 ट्रंप हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की चूक के बाद कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें एजेंटों पर कार्रवाई और प्रक्रियागत बदलाव शामिल हैं। ये कदम सीनेट रिपोर्ट (2025) के बाद तेज हुए। वहीं, एजेंटों पर कार्रवाई हुई। 6 एजेंटों को सस्पेंड किया, 10-42 दिनों की सैलरी कटौती और गैर-ऑपरेशनल पदों पर स्थानांतरित। पूर्व डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दिया। वहीं, प्रक्रियागत सुधार किए गए। स्थानीय पुलिस/एजेंसियों के साथ समन्वय, संचार और सुरक्षा मैनुअल को संशोधित। हवाई निगरानी के लिए अलग डिवीजन, खतरे मूल्यांकन में स्पष्ट जिम्मेदारियां।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582083548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

सात ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने भारत गौरव ट्रेन रवाना

गोरखपुर। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड सात ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के लिए गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन सोमवार की सुबह 9 बजे रवाना हो गई। इसके पूर्व आईआरसीटीसी के कर्मचारियों ने यात्रियों का तिलक लगाकर का स्वागत किया। यह ट्रेन आठ मई को शाम 4:30 बजे वापस आएगी। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), द्वारकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात), त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (गुजरात), घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (संभाजी नगर) दर्शन का अवसर मिलेगा।

21 बेटियों के हाथ पीले कर छलके खुशी के आंसू, 24वें वर्ष सामूहिक विवाह में सेवा, संवेदना और संस्कार का दिखा अनुपम संगम

कुशीनगर।

केडी शाही जनजागृति संस्थान, तुर्कपट्टी महुअवा द्वारा आयोजित 24वें वर्ष सामूहिक विवाह समारोह में 21 निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह वैदिक रीति-रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। मांग में सिंदूर, आंखों में सपने और परिजनों की नम आंखों के बीच 21 बेटियां नए जीवन की दहलीज पर विदा हुईं तो पूरा पंडाल भावुक हो उठा। संस्थान द्वारा पिछले 24 वर्षों से निरंतर यह सामाजिक आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 650 से अधिक निर्धन बेटियों के हाथ पीले कराए जा चुके हैं। इस वर्ष भी बद्दू, करीना, पुष्पा, सुमन राजभर, सोनिया कुशवाहा सहित 21 कन्याओं का विवाह विजय कुमार, सोनू कुमार, अजय राजभर, विपिन कुशवाहा समेत 21 वरों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रबंधक सुधीर शाही ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सम्मानपूर्वक विवाह कराना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल विवाह नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक सहयोग और संवेदना का उत्सव है। कार्यक्रम के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि यह पुनीत कार्य सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि संस्थान के 25वें वर्ष पर 51 निर्धन कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र शुक्ला एवं डॉ. सीबी सिंह ने व्यवस्थाओं की कमान संभाली, जबकि स्वागताध्यक्ष श्रीमती कंचन गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में सदर विधायक मनीष जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, डॉ. देवेंद्र मोदी, मनोज शर्मा, राजेश सिंह, सचिन चौरसिया, प्रदीप चौरसिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में समाजसेवियों, चिकित्सकों और क्षेत्रीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। डॉ. अभिषेक शुक्ला, डॉ. गिरिजेश जायसवाल, डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. अरुण गौतम, किरण जायसवाल, डॉ. सुनीता पांडेय, मीनू जिंदल, रश्मि श्रीवास्तव, विनीत गुप्ता और डॉ. कालिंदी त्रिपाठी ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया।

24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

कुशीनगर।

थाना पटहेरवा क्षेत्र में दर्ज चोरी के एक मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 26 अप्रैल 2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2026, धारा 305(ए) बीएनएस से संबंधित मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को चोरी गए सामान के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 331(4) एवं 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहिल पुत्र अनवर, निवासी महुअवा कांटा, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक बोरी ब्रान और एक बैटरी बरामद होने की बात कही गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना पटहेरवा में पूर्व से मारपीट, धमकी और चोरी से जुड़े तीन मुकदमे दर्ज हैं। मामले में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय, उपनिरीक्षक विशाल कुमार, हेड कांस्टेबल रामप्रवेश यादव, कांस्टेबल अल्तमस तथा कांस्टेबल विनोद कुशवाहा शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है।

भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर बड़ी कार्रवाई 25 क्विंटल से अधिक विदेशी अखरोट बरामद, ट्रक समेत चालक गिरफ्तार

- काठमांडू से दिल्ली के लिए जा रहे ट्रक कंटेनर में 7 लाख रुपए का विदेशी अखरोट बरामद

महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा सोनौली पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार, पिलर संख्या 517/2 के पास पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में विदेशी अखरोट की तस्करी का पर्दाफाश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 22वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट सैफवान एन. और पुलिस चौकी सोनौली प्रभारी गौरव यादव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। टीम ने नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध ट्रक को सीमा से करीब 10 मीटर अंदर रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कंटेनर ट्रक संख्या ऋ्14ऌ 5722 में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त केबिन से 103 बोरी विदेशी अखरोट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 2570 किलोग्राम बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि यह ट्रक नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जा रहा था। मौके पर चालक को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान हरियाणा निवासी साहिब खान के रूप में हुई है। बरामद अखरोट, ट्रक और आरोपी को आगे की विधिक कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम विभाग को सुपुर्द करने की प्रक्रिया जारी है। सीमा पर इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़े अवैध नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। इस सम्बंध में सहायक कमांडेंट ने बताया कि ट्रक सीज कर माल सहित आरोपी को अग्रिम कार्यवाही के लिए कस्टम विभाग को सौप दिया गया है।

कुरआन-ए-पाक तमाम मामलों में मार्गदर्शन करने वाली आखिरी किताब - शहर काजी

गोरखपुर।

रविवार को जामिया अल इस्लाह एकेडमी नौरंगाबाद गोरखनाथ में इस्लामी बहनों के लिए साप्ताहिक दर्स-ए-कुरआन (सबक/ शिक्षा) की शुरूआत की गई। यहां कुरआन-ए-पाक की शिक्षा प्रत्येक रविवार को दोपहर साढ़े तीन बजे से दी जाएगी। वहीं मकतब इस्लामियात तुर्कमानपुर में भी कुरआन-ए-पाक का दर्स दिया गया। यूपी बोर्ड की दसवीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली हफ्सा अली व सदफ फातिमा को सम्मानित किया गया। दर्स की शुरूआत करते हुए शहर काजी मुफ्ती मुहम्मद अजहर शम्सी ने कहा कि कुरआन-ए-पाक का दर्स (सबक/ शिक्षा) मूल रूप से कुरआन की आयतों को पढ़ने, उनके अर्थ को समझने और उन पर चिंतन करने की प्रक्रिया है।

इसका मुख्य उद्देश्य अल्लाह के संदेश को जानकर उसे अपने जीवन में उतारना है। कुरआन इंसानी जिंदगी के तमाम मामलों में मार्गदर्शन करने वाली आखिरी किताब है। यह इंसान के चरित्र का सुधार करती है और उसे आध्यात्मिक तौर पर पवित्र बनाती है। दर्स का एक बड़ा मकसद

नौरंगाबाद गोरखनाथ में इस्लामी बहनों के लिए दर्स-ए-कुरआन की शुरूआत

लोगों को अरबी भाषा न आने के बावजूद उर्दू व हिंदी में अल्लाह का संदेश पहुंचाना है। दर्स संचालक हाफिज रहमत अली निजामी ने कहा कि कुरआन-ए-पाक का शिक्षा इंसान के लिए अल्लाह का संदेश है जो ईमान, नैतिकता, न्याय और समानता पर जोर देती है। यह कुरआन-ए-पाक के अर्थ, व्याख्या और मानव जीवन के लिए इसके मार्गदर्शन को समझने का एक प्रयास है। दर्स न केवल पढ़ने, बल्कि इसे समझने और जीवन में उतारने के लिए होता है। संयोजक कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी व आसिफ महमूद ने कहा कि कुरआन-ए-पाक का दर्स हमें आत्म-सुधार, सामाजिक जिम्मेदारी, नमाज, जकात, और तौहीद के माध्यम से अल्लाह की इबादत सिखाता है। दर्स में कुरआन का गहरा अध्ययन व्याख्या के साथ किया जाता है ताकि आयतों का सही अर्थ समझा जा सके। दर्स व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक रिश्ते, और सामाजिक आचरण के लिए सीधे और व्यावहारिक नियम प्रदान करता है। अंत में दुरूद ओ सलाम पढ़कर मुल्क में अमन व शांति की दुआ मांगी गई। दर्स में शीरीन आसिफ, आयशा खातून, सैयदा यासमीन, नाजिया खातून, या वारसी, शिफा खातून, सना फातिमा, फिजा खातून, शालिबा, मुबस्सिरा, आस्मा खातून, नूरजहां, फिजा खातून, सानिया, अदीबा, गुलफिशा सहित तमाम इस्लामी बहनों की सहभागिता रही।

एआई रोजगार बढ़ाने वाला टूल, छात्रों के लिए बना पॉकेट टीचर

जागृति के बरगद सभागार में एआई स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप, छात्रों को दी गई तकनीकी जानकारी

देवरिया।

जागृति उद्यम केंद्र - पूर्वांचल की ओर से सोमवार को बरपार स्थित बरगद सभागार में एआई स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और सरस्वती सीनियर सेकेंड्री विद्या मंदिर, देवरिया खास के छात्रछात्राओं ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग और संभावनाओं से परिचित कराना था।

कार्यशाला में एक्सपर्ट ओम आशीष मिश्रा ने छात्रों को एआई की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब एआई की शुरूआत हुई थी, तब यह आशंका जताई जा रही थी कि इससे रोजगार कम होंगे, लेकिन वर्तमान समय में यह रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे एआई के साथ तालमेल बैठाकर अपने कौशल को विकसित करें।

एआई छात्रों के लिए पॉकेट टीचर की तरह काम कर सकता है। यदि छात्र स्कूल में पढ़ाई के बाद घर पर एआई का उपयोग करके विषयों को गहराई से समझें, तो उनके ज्ञान और कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने प्रॉम्प्ट, कम्प्लीशन, कॉन्टेक्स्ट विंडो और एपीआई जैसे तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि एआई प्लेटफॉर्म पर आधार कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य निजी दस्तावेज साझा नहीं करने चाहिए। जागृति के इन्क्यूबेशन निदेशक विश्वास पांडेय ने कहा कि यह एआई का दौर है। एआई सीखने के साथ रोजगार सृजन का भी सशक्त माध्यम बन रहा है।

कौन हैं ओम आशीष मिश्रा

आईआईटी कानपुर से जुड़े जेन एआई शोधकर्ता ओम आशीष मिश्रा पिछले तीन वर्षों से डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे ब्लिसफुल एनर्जी के संस्थापक होने के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक मंचों पर एआई विशेषज्ञ और वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, हिताची और एचएसबीसी जैसी कंपनियों के साथ काम किया है और तीन बार गूगल तथा छह बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाणित प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा वे एमआईटी इनोवेशन बूटकेंपर और

मानवता की मिसाल तविन फाउंडेशन ने दो बेटियों के हाथ पीले करने में की मदद

फरेन्दा महराजगंज।

सामाजिक सरोकारों में अग्रणी तविन फाउंडेशन ने प्रतिबद्धता दोहराते हुए दो जरूरतमंद युवतियों के विवाह में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

सुखना देवी पत्नी घरभरन ग्राम झावा कोट पोस्ट बारातगाड़ा जिला महाराजगंज अपनी बेटी कविता की शादी को लेकर बेहद चिंतित थी सुखना देवी व उनके बच्चे मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं ऐसे में बेटी कविता की शादी का खर्च किसी पहाड़ जैसा लग रहा था वहीं दूसरा परिवार संगम कुमारी यादव पुत्री श्री बहादुर यादव ग्राम गोपालपुर दुबे पोस्ट पोखरभिंडा जिला महाराजगंज की भी शादी तय हो चुकी है परंतु परिवार की माली हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है परिवार के अधिकांश सदस्य दिव्यांग भी है जब इन दोनों परिवार के लोगों को तविन फाउंडेशन की ÷माया शुभ मंगल संकल्प÷ योजना के बारे में पता

चला तो उन्होंने आनंद नगर स्थित कार्यालय में संपर्क कर इस योजना में आवेदन किया। आवेदन आने के उपरांत तविन फाउंडेशन के कार्यकारी सदस्य नरेंद्र नाथ त्रिपाठी,अरविंद कुमार वर्मा,धीरेंद्र कुमार राय व अमित जायसवाल द्वारा विवाह की पुष्टि कराने के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष ततसत मणि त्रिपाठी द्वारा इन परिवारों को फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक परिवार को ?21000 की अनुदान राशि सीधे उनके खाते में प्रदान की गई। संस्था के अध्यक्ष ततसत मणि त्रिपाठी ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना है ताकि संसाधनों के अभाव में किसी बेटी की शादी ना रुक सके। इस अवसर पर फाउंडेशन के कार्यकारी सदस्य नरेंद्र नाथ त्रिपाठी अरविंद कुमार वर्मा धीरेंद्र कुमार राय ,अधिवक्ता अमित जायसवाल, प्रद्युमन सिंह,ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील यादव, अधिवक्ता अखिलेश यादव ,अवधेश यादव ,बैजनाथ यादव, रामनाथ निषाद, संदीप कुमार, राजीव यादव आदि अन्य लोग मौजूद रहे।

दिल्ली में आसमान से बरस रही आग, पारा 40 के पार, जानें कब होगी राहत की बारिश

नई दिल्ली। दिल्ली में इस समय दिन के साथ रातें भी लगातार गर्म हो रही है। दोपहर के समय तो ऐसा लगता है जैसे भट्टी जल रही हो। रविवार सुबह से ही तपती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। इससे लोगों का हाल बेहाल रहा और वह परेशान दिखे। हालात ऐसे थे कि रात में भी सुकून नहीं मिला। दिन और रात के समय गर्म हवाएं चली। मौसम विभाग ने पहले ऑरेंज फिर शाम तक लू का यलो अलर्ट जारी किया हुआ था। इस दौरान अधिकतम तापमान 42.1 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं, लगातार पांच दिन से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा और लू की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, और उसके बाद के तीन दिन में इसमें 4-6 डिग्री की गिरावट आएगी और उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं, अगले तीन दिन के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में लू की स्थिति महसूस की गई। ऐसे में लू का यह लगातार तीसरा दिन रहा। इन स्थितियों के अगले 24 घंटे तक जारी रहने की आशंका है। उन्होंने बताया कि निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर पूर्वी हवाओं के चलने के प्रभाव से अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे 28 अप्रैल से इस क्षेत्र में लू की स्थिति में कमी आएगी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और बदलते मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री और न्यूनतम 26-28 डिग्री रहने की संभावना है। इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे और लू जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लू का यलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही, दोपहर बाद गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 30-40 किमी प्रति घंटे और झोंकों में 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यही नहीं, 28 अप्रैल को राहत की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान घटकर 40-42 डिग्री और न्यूनतम 27-29 डिग्री रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान धीरे-धीरे पूरी तरह बादलों से घिर सकता है और गरज, बिजली और तेज हवाओं 30-40 किमी प्रति घंटे, झोंकों में 50 किमी प्रति घंटे के साथ हल्की बूंदाबांदी संभव है। मौसम विभाग के अनुसार, 29 अप्रैल को भी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री और न्यूनतम 25-27 डिग्री रहने की संभावना है। साथ ही, आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज-चमक व तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। वहीं, 30 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री तक गिर सकता है। दिन में आंशिक बादल और शाम के समय गरज के साथ बादल बनने की संभावना है। इसके अलावा, 1 और 2 मई को अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23-25 और 24-26 डिग्री रहने का अनुमान है, इन दिनों आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।

आप बनाम बीजेपी- सात सांसदों के विलय पर कानूनी लड़ाई के संकेत, संजय सिंह ने खुले तौर पर दी चेतावनी

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने सात पूर्व राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर इन सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया तो पार्टी अदालत का रुख करेगी।

सभापति पर लगाया ये आरोप

संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सातों सांसदों द्वारा भाजपा में विलय के लिए दिया गया पत्र स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आप की आपत्तियों और दसवीं अनुसूची (एंटी-डिफेक्शन कानून) के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सभापति ने उन सात सांसदों के पत्र को आधार बनाकर विलय स्वीकार कर लिया, जबकि हमारी आपत्ति और अयोग्यता की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है।

अदालत जाने की दी चेतावनी

आप नेता ने उम्मीद जताई कि जब उनकी पार्टी का पत्र विस्तार से देखा जाएगा तो संविधान और लोकतंत्र के हित में इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी अदालत जाएगी। संजय सिंह ने इसे गलत तरीके से पार्टी तोड़ने का मामला बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

कानूनी मोड़ ले सकता है पूरा विवाद

गौरतलब है कि शुक्रवार को आप को बड़ा झटका लगा था, जब उसके 10 में से सात राज्यसभा सांसद- राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंदर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालिवाल ने पार्टी छोड़कर भाजपा में विलय का एलान किया था। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि आप अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों से भटक गई है।

हरियाणा में बड़ा हादसा- चलती बस में लगी आग, अंदर सवार थे 40 यात्री; चार लोग झुलसे, दो आईसीयू में भर्ती

भिवानी।

हरियाणा के भिवानी स्थित गांव मिलकपुर में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे यात्रियों से भरी निजी बस में आग लग गई। बस में 30 से 40 यात्री सवार थे। इनमें से चार बुरी तरह झुलस गए। दो की हालत गंभीर है इनमें से दो को अग्रोहा रेफर किया। निजी बस भिवानी से सवारियां भरकर हांसी की तरफ जा रही थी। मिलकपुर गांव के पास इसमें से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। इससे सवारियों में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही भिवानी और हांसी से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई। आग से झुलसे लोगों को हांसी के निजी अस्पताल भिजवाया गया। यहां से दो लोगों को आईसीयू में रखा गया है जबकि दो को अग्रोहा रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही बवानीखेड़ा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि आग से करीब 12 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं।

महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46.9डिग्री, देश में सबसे गर्मबिहार में गर्मी से 2 और आंधी-बिजली से 5 मौतें

नई दिल्ली। देश में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में रविवार को तापमान 46डिग्रीके पार चला गया। महाराष्ट्र का अकोला 46.9डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। अमरावती 46.8डिग्री, बांदा 46.6डिग्री, वर्धा और बाड़मेर 46.4डिग्री, जैसलमेर और यवतमाल 46पहर तापमान के साथ हीटवेव की चपेट में है। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार तापमान 45डिग्री पहुंचा। इंदौर-भोपाल में भी पारा 43डिग्री पर बना हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 8 जिलों में रविवार को पारा 40डिग्री के पार चला गया। यहां गर्मी से दो मौतों की खबर है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई।

पीएम मोदी ने बंगालवासियों के नाम लिखा पत्र

कहा- भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए; सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों के नाम एक पत्र और एक ऑडियो संदेश जारी किया है। बता दें कि, राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा और इसके नतीजे 4 मई को जारी होंगे। पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अपने परिवारजनों का जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यहां की युवाशक्ति हो या नारीशक्ति, हमारे किसान भाई-बहन हों, श्रमिक या फिर कारोबारी, सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। मैंने इस पत्र में उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यवासियों के नाम एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है, जो हिंदी और बंगाली भाषा में अलग-अलग जारी किया गया है। पीएम मोदी ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है। उन्होंने बंगाल के लोगों से 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया। यह लोकतंत्र के मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने सभी के मिलकर बंगाल को विकसित बनाने की बात कही, जिसे उन्होंने मोदी की गारंटी बताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान डाले गए हैं, जिसमें रिकॉर्ड 92.15 फीसदी वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे।

चिलचिलाती गर्मी पर राहत की फुहार -28 अप्रैल से एक मई तक दिल्ली-यूपी-बिहार समेत कई रायों में बारिश के आसार

नई दिल्ली। चिलचिलाती गर्मी से जल्द राहत मिलने के संकेत हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश तक मौसम का मिजाज तेजी से बदलने जा रहा है, जहां अगले लगभग एक सप्ताह तक छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार-झारखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार है, जिससे तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट आएगी और भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके प्रभाव से देश के करीब आधे हिस्से के मौसम में व्यापक बदलाव दिखेगा। 28 अप्रैल से 1 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है, जिससे आंधी-तूफान जैसे हालात भी बन सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी में अचानक बारिश की स्थिति बनने के बारे में स्काइमेट ने दो कारण बताए हैं।

पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ-साथ वर्तमान में महाराष्ट्र के ऊपर एक हीट जोन बना हुआ है, जो धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगा है। इससे उत्तर भारत में मौसम के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बन रही वर्षा प्रणाली उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। इसके चलते राजस्थान में बादलों की सक्रियता बढ़ गई है और धूल भरी आंधी का दायरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तीन मई तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में मौसम की यह सक्रियता मैदानी इलाकों के मौसम को भी प्रभावित करेगी। राजस्थान के कुछ पॉकेट में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक मई तक गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले तीन-चार दिनों के दौरान अलग-अलग हिस्सों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। बिहार और बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की भी आशंका जताई गई है, जिससे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम के बदलाव से तापमान में औसतन तीन से चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि सोमवार तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू का असर बना हुआ था, मगर इसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी पर किया हमला, 4 लोगों की मौत; मासूम बचों समेत 70 घायल

नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने सोमवार को अफगानिस्तान पर मोर्टार और रॉकेट से हमले किए। इन हमलों में चार लोग मारे गए हैं और 70 लोग घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन दावों को झूठ बताकर खारिज कर दिया है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला ने बताया कि कुनार प्रांत के असदाबाद में घरों और सैयद जमालुद्दीन अफगानी विश्वविद्यालय को निशाना बनाकर किए गए हमलों में घायल लोगों में 30 छात्र, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

अक्षम्य युद्ध अपराध घोषित

हमदुल्ला ने एक्स पोस्ट किया, हम पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें आम लोगों को निशाना बनाया गया था। अफगानिस्तान ने इन हमलों को अक्षम्य युद्ध अपराध घोषित किया है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने पोस्ट में कहा कि विश्वविद्यालय पर कोई हमला नहीं हुआ है। ये दावे निराधार हैं। गौरतलब है कि फरवरी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बीच उस समय भीषण संघर्ष छिड़ गया था, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। इस्लामाबाद ने कहा कि उसने आतंकी गढ़ों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाया है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद आंतरिक समस्या है। तालिबान के अनुसार पिछले महीने काबुल में एक नशामुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों में शांति वार्ता शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे चीन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उरुमकी में हुई शांति वार्ता के दौरान वे अपने संघर्ष का व्यापक समाधान खोजने पर सहमत हुए थे। उरुमकी में वार्ता की घोषणा के बाद से झड़पें कम हो गई हैं, लेकिन कुछ छोटी-मोटी झड़पों की खबरें आई हैं।

लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी, एलजी वीके सक्सेना ने किया एलान

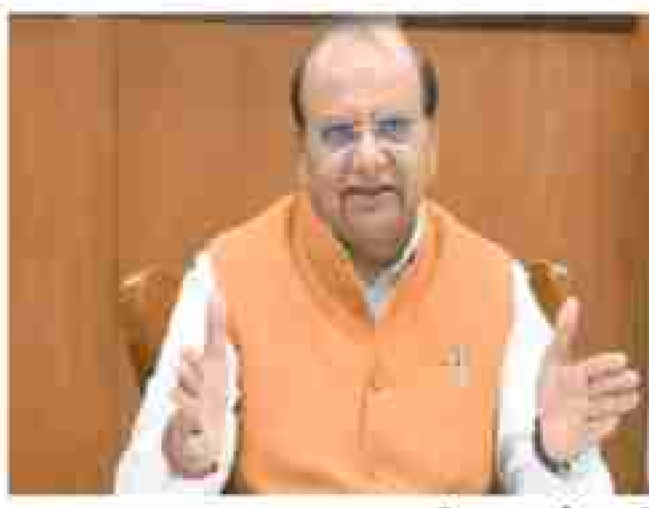

लद्दाख।

लद्दाख में पांच नए जिलों की अधिसूचना जारी हो गई है। इसकी जानकारी खुद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दी।

उन्होंने लिखा कि लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जा रहा है।

नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, इन पांच नए जिलों के गठन के साथ, लद्दाख में अब दो के बजाय सात जिले हो जाएंगे। यह विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है। गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पहले ही अनुमोदित इस परिवर्तनकारी निर्णय से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूती मिलेगी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और लद्दाख के लोगों, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों को सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी। नए जिलों के गठन से, शासन को नागरिकों के करीब लाने के अलावा, विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय से लद्दाख के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर एक उज्ज्वल, मजबूत और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

दिल्ली के चार स्कूलों को बम की धमकी, एक आर्मी तो एक सीआरपीएफ का स्कूल भी शामिल; भेजा गया था ईमेल

नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को चार स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इन धमकियों से स्कूलों में दहशत फैल गई। हालांकि, बाद में दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने इसे फर्जी बताया।

अधिकारी के अनुसार, अलर्ट मिलते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। स्थानीय पुलिस और स्कूल अधिकारियों के साथ मिलकर तलाशी और निकासी अभियान चलाया गया। टीमों ने परिसरों की गहन जांच की। किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

सभी धमकियों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली, उनमें धौला कुआं, दिल्ली कैंट और शंकर विहार स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल शामिल हैं। इनके अलावा द्वारका सेक्टर 14 स्थित सीआरपीएफ स्कूल भी शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एहतियात के तौर पर तलाशी के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों ने आगे कहा कि ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। साइबर सेल की टीमें इन ईमेल के पीछे के लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन धमकियों के पीछे किसका हाथ है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बंगाल में थमा चुनावी शोर- भाजपा बोली- टीएमसी ने घुसपैठियों का गढ़ बनाया; ममता ने राज्य को बांटने का लगाया आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया। यह चुनाव घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई से प्रभावित रहा। दोनों दलों ने 142 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से कई वादे किए। इस जोरदार प्रचार अभियान के दौरान, भाजपा नेतृत्व ने सत्ताधारी टीएमसी पर पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बनाने का आरोप लगाया। वहीं, ममता बनर्जी ने भगवा दल पर विभाजनकारी राजनीति करने, राज्य को बांटने का प्रयास करने और मछली व अंडे के सेवन को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया।

भाजपा का प्रचार और आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने राज्य में प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी पर कानून व्यवस्था बिगड़ने, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, राजनीतिक अशांति, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया।

मोदी ने मतुआ समुदाय से संपर्क साधा और उनसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर टीएमसी के झूठ से गुमराह न होने का आग्रह किया। उन्होंने सभी शरणार्थियों को देश में स्थायी निवास का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर पशु तस्करी रोकने और मवेशियों की रक्षा के लिए एक विशेष दस्ता बनाया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हुए गुंडा राजऔर सिंडिकेट राज खत्म करने का वादा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी गई थी। शाह ने 4 मई के बाद भाईपो कर खत्म करने और महिलाओं व बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता तथा राज्य परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया।

टीएमसी का पलटवार और वादे

टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। इनमें हर बैंक खाते में 15 लाख रुपये और सालाना दो करोड़ नौकरियां जैसे वादे शामिल हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद अपनी एक रैली में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने सत्ता बरकरार रखने का विश्वास व्यक्त किया। बनर्जी ने शाह पर चुनाव के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्हें उल्टा लटका देंगे वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने एक संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी चिंता जताई और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कथित ज्यादतियों के खिलाफ चेतावनी दी।

चुनाव आयोग की तैयारियां

29 अप्रैल को होने वाले इस चरण के चुनाव में कुल 3,21,73,837 मतदाता मतदान के पात्र हैं। इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिलाएं और 792 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। मतदान 41,001 केंद्रों पर होगा, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें सात जिलों में केंद्रीय बलों की 2,321 कंपनियां तैनात की गई है।

कुल 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कैमरा लगे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता में केंद्रीय बलों की सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात की गई हैं।